DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS THE INDIAN EXPRESS, TUESDAY, DECEMBER 20, 2022

Elevated corridor in pipeline to ease traffic between north, central Delhi

GAYATHRI MANI
NEW DELHI, DECEMBER 19

THE PUBLIC Works Department (PWD) is planning to construct an elevated corridor on GT Road, between Tripolia Gate and Rani Jhansi road, with an aim to end heavy traffic jams at junctions and key intersections on the stretch and provide seamless connectivity between North and Central Delhi.

According to a senior PWD official, GT Road is one of the key stretches that connects the Outer part of the national capital to North and Central Delhi. "The 3.5-4 km-long stretch from Tripolia Gate to Rani Jhansi Road is heavily congested. A proposal has been made for an integrated corridor development plan for decongestion," said an official.

Officials said the plan will address three key intersections on this stretch: Shakti Nagar Chowk, Ghanta Ghar and Sabji Mandi. "All three are heavily congested and have narrow lanes which makes commuting, especially during peak hours, very difficult. At Ghanta Ghar and Sabji Mandi, due to improper parking, vendors, pedestrians, traffic is slow even during non-peak hours."

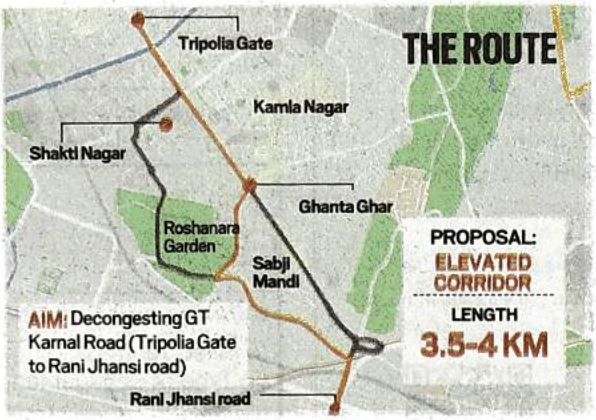

The PWD is also planning a solution for vehicular parking and pedestrian paths on this stretch to decongest the three intersections. However, with construction for another project already underway – the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) is constructing a double-deck flyover-cum-metro corridor at Azadpur Chowk between GT Karnal Road and Rani Jhansi Road – officials will have to find a way to manoeuvre around it.

The department had earlier moved a proposal to decongest the intersections but it was rejected by UTTIPEC. "The roads are narrow, so it is very difficult to execute the project even now. But the department has plans to construct an elevated corridor. Before that, a detailed study will be conducted to check feasibility on ground," said an official.

Once appointed, a consultancy agency will do feasibility and comprehensive surveys to find the number and modes of vehicles including pedestrian and non-motorised vehicles, present and future transportation proposals (Metro/ BRT/ NHAI/PWD/DDA/Railways) along and around the influence zone.

"During the study, an integrated transit corridor development plan with detailed design of intersections, middle sections having entry and exits, all arterial and major traffic movement corridors will be prepared," said the official.

"Once the feasibility study is done, the PWD will move a proposal to construct the elevated corridor. The length, width and number of lanes will be decided only after the study. Tenders have been floated to hire consultancy agencies and the process will take about a month. Once the plans are approved and the stretch is constructed, commuters will get major relief," added the official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 20 दिसंबर 2022 ED----------

अनधिकृत कॉलोनियों में पेंडिंग काम 3 महीने के अंदर पूरा करें: सिसोदिया

सिसोदिया ने विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों को दिए निर्देश

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कॉलोनियों में पेंडिंग पड़े विकास कार्यों को तीन महीने में पूरा करें। इन कामों में बजट की कमी आड़े ना आए, इसके लिए बजट भी बढ़ाकर डबल किया जा रहा है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट बनाकर जल्द से जल्द काम पूरे करवाएं। सभी विकास कार्य तेज गति से पूरे हों, इसके लिए हर 15 दिन में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी, जिसमें संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी कि कितना काम पूरा हुआ और कितना बाकी है।

सोमवार को उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग और इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इन विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कॉलोनियों में विकास कार्य अंतिम चरण में हैं, वहां सभी

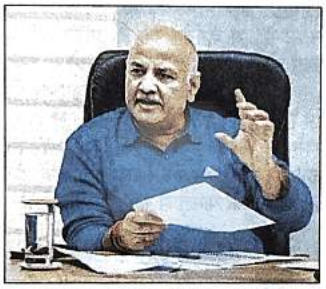

उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

कामों को 3 महीने के अंदर पूरा किया जाए और बची हुई कॉलोनियों में भी जल्द से जल्द विकास कार्य शुरू करवाए जाएं।

सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें दिल्ली सरकार विकास कार्य करवा रही है। पिछले 4 साल में 60 विधानसभाओं की लगभग 1100 अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य या तो पूरे हो चुके हैं या फिर अपने अंतिम चरण में हैं। विकास कार्यों के तहत इन कॉलोनियों में सड़कें, गलियां और नालियां बनवाने, सीवर और पानी की नई लाइनें डलवाने और स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम किया गया है। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में कुल 3,767 किमी लंबी गलियों और 5203 किमी लंबी नालियों का निर्माण किया गया है।

हो रहा विकास

- सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें दिल्ली सरकार विकास कार्य करवा रही है
- पिछले 4 साल में 60 विधानसभाओं की लगभग 1100 अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य या तो पूरे हो चुके हैं या फिर अपने अंतिम चरण में हैं

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने अनधिकृत कॉलोनियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा और उनमें रहने वाले लाखों लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवाई। अब सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम दिल्ली के एक-एक व्यक्ति को शानदार सुविधाएं और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सिसोदिया का दावा है कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की तस्वीर बदलने के लिए दिल्ली सरकार युद्धस्तर पर काम करवा रही है, जिसके चलते अब इन कॉलोनियों में लोगों को बदलाव दिख रहा है। कुछ साल पहले तक अनधिकृत कॉलोनियां की स्थिति काफी दयनीय थी, लेकिन आज इन कॉलोनियों में भी अधिकृत कॉलोनियों जैसी ही सुविधाएं मौजूद हैं।

300 कॉलोनियों में अब भी काम होना बाकी

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में लगभग 300 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें विभिन्न कारणों के चलते विकास कार्य नहीं किए जा सके हैं। इन कॉलोनियों में एएसआई या डीडीए से एनओसी नहीं मिलने, फॉरेस्ट लैंड होने, ओवरलैपिंग होने के कारण दिल्ली सरकार विकास कार्य शुरू नहीं करवा पाई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इन कॉलोनियों में कुछ कॉलोनियां ऐसी भी हैं, जहां नालियों-गलियों की स्थिति पहले से ही अच्छी है या फिर उन्हें किसी अन्य एजेंसी द्वारा डिवेलप किया जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- Hindustan Times -DATED- 20/12/2022

{ SISODIA SAYS AFTER REVIEW MEETING }

'In 7 yrs, govt built 3,767km roads in unauthorised areas'

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi government has constructed 3,767km of roads and 5,203km of drains in unauthorised colonies in the last seven years, deputy chief minister Manish Sisodia said after a review meeting with senior officials of Irrigation and Flood Control Department (I&FC) and Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC) on Monday.

Sisodia directed officials to complete pending work in unauthorised colonies in the next three months, and told them that he will review the progress of work every 15 days, people aware of the matter said.

The deputy chief minister, who also holds the Public Works Department portfolio, stated that the Aam Aadmi Party government is working on a war footing to ensure proper roads and drainage systems in nearly 1,800 unauthorised colonies.

According to officials, of the 1,800 unauthorised colonies, development works in about 1,100 are either in their final stages or have been completed.

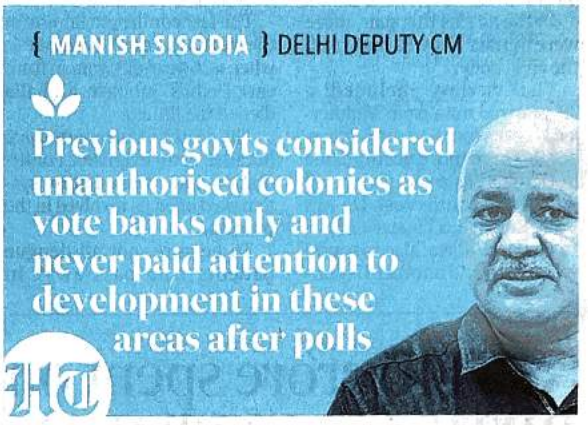

"The Delhi government is determined to provide residents of unauthorised colonies across the city with basic civic infrastructure. Previous governments considered the unauthorised colonies as vote banks only and never paid attention to development in these residential areas after elections," Sisodia said.

The civic infrastructure in the unauthorised colonies of Delhi, spread almost across the Capital, are in bad shape due to the absence of roads, drainage and sewer lines.

According to an official, development works could not be carried out in around 300 unauthorised colonies due to various reasons such as the unavailability of NOCs from the archaeological department and the Delhi Development Authority because the colonies are located on lands belonging to different agencies.

Some of them are already developed and have the basic civic infrastructure, or they are being developed by other agencies, the officials added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 20 दिसंबर, 2022

दिल्ली जागरण

अनधिकृत कालोनियों की बदली सूरत : सिसोदिया

60 विधानसभा क्षेत्रों की 1100 अनधिकृत कालोनियों में बनी सड़कें और नालियां

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों की सूरत बदलने की दिशा में दिल्ली सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के अनधिकृत कालोनियों में शानदार मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के मिशन के तहत चार साल में लगभग 1100 अनधिकृत कालोनियों के विकास कार्य शुरू कराए गए, इसमें ज्यादातर पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कालोनियां हैं।

सिसोदिया ने सोमवार को बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग व उद्योग दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम के उच्चाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछली सरकारों ने अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक के रूप में देखा व चुनाव के बाद यहां काम करवाने के बजाय कन्नी काटते रहे। उनके नेता यहां आते थे और वादे करके चले जाते थे, लेकिन उनकी सरकार ने कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने शानदार सड़कें-गलियां, जल-निकासी को चौड़ी नालियां बनवाने की गारंटी दी थी, जिसे हम पूरा कर रहे हैं।

अनधिकृत कालोनियों के विकास कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ● सौजन्य -दिल्ली सरकार

3767 किलोमीटर गलियां व 5203 किमी नालियां चार साल में सरकार ने बनाई

एनओसी व अन्य वजह से कई कालोनियों में नहीं हो सका काम

अधिकारियों ने सिसोदिया को बताया कि मौजूदा समय में लगभग 300 ऐसी अनधिकृत कालोनियां हैं, जहां विभिन्न कारणों की वजह से विकासात्मक कार्य नहीं कराए जा सके हैं। इनमें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, डीडीए से एनओसी न मिलने, फारेस्ट लैंड जैसे कारण शामिल हैं। इनमें बहुत सी ऐसी हैं, जहां नालियों-गलियों की स्थिति पहले से ही अच्छी है या फिर उसे किसी अन्य एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है।

तीन माह बचा काम पूरा किया जाएगा: सिसोदिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कालोनियों में विकासात्मक कार्य अपने अंतिम चरण में हैं उसे तीन महीने के अंदर पूरा किया जाए। साथ ही बची कालोनियों में भी विकास कार्य जल्द शुरू किया जाए। सिसोदिया अब हर 15 दिनों में अधिकारीयों के साथ कार्य की प्रगति कि समीक्षा करेंगे।

हिन्दुस्तान

कच्ची कॉलोनियों को लेकर समीक्षा

बैठक

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में विकास कार्यों को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग तथा इंडस्ट्री एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

इसमें अधिकारियों ने बताया कि पिछले चार साल में दिल्ली की लगभग 1100 अनधिकृत कॉलोनियों के विकास का कार्य या तो पूरा हो चुका है या फिर अपने अंतिम चरण में है। इसके तहत इन कॉलोनियों में सड़कें, गलियां व नालियां बनवाने, सीवर व पानी की लाइनें डलवाने का काम किया गया है। दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं।

तीन माह में पूरे करें विकास कार्य : सिसोदिया

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन कॉलोनियों में विकासात्मक कार्य अपने अंतिम चरण में है उसे तीन महीने में पूरा किया जाए। बची कॉलोनियों में भी विकास कार्य जल्द शुरू किया जाए। सिसोदिया अब हर 15 दिनों में अधिकारियों के साथ कार्य की प्रगति कि समीक्षा करेंगे। दिल्ली सरकार अब तक इन अनधिकृत कॉलोनियों में 3767 किलोमीटर गलियों व 5203 किमी नालियों का निर्माण करा चुकी है।

विपक्ष पर साधा निशाना : सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने को प्रतिबद्ध है। पिछली सरकारों ने अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक के रूप में देखा और चुनाव के बाद यहां काम करवाने के बजाय कन्नी काटती रहीं। उनके नेता यहां आते थे और वादे करके चले जाते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ने इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने शानदार सड़कें-गलियां, जल-निकासी के लिए चौड़ी नालियां बनवाने की गारंटी दी थी और हम गारंटियों को पूरा कर रहे हैं।

300 कॉलोनियों में काम नहीं कराया जा सका : अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में लगभग 300 अनधिकृत कॉलोनियां में विभिन्न कारणों से विकास कार्य नहीं किया जा सका है। इनमें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, डीडीए से एनओसी न मिलने, फारेस्ट लैंड होने, ओवरलैपिंग होने के कारण दिल्ली सरकार द्वारा काम शुरू नहीं हो सके हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, DECEMBER 20, 2022
NEWSPAPERS DATED

Delhi To Plan In Advance So That It Doesn't Rain On Its G20 Parade

With Most Events Scheduled For September, Focus On Curbing Waterlogging

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: With six of the eight G-20 events, including the main summit, scheduled to be held in the city at the peak of the monsoon next September, the government has underscored the need to put in place foolproof and permanent measures to prevent waterlogging along arterial roads.

According to officials, a team of four road-owing agencies — Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Corporation, Public Works Department and National Highways Authority of India — has been formed to identify flooding hotspots around the proposed venues of the summit and other events and take location-specific measures to ensure water drains out immediately even if there is a heavy downpour.

Traditionally, August is the wettest month in the capital but the last few years witnessed a flurry of rainfall even in September, when monsoon starts receding. Between September 1 and 24 this time, Delhi witnessed incessant rain, receiving 111.6mm of rainfall. September's rainfall tally was 164.5mm - more than 33% over the normal monthly mark of 123.5mm.

Six important G-20 events - fourth sherpa meeting (September 3-6), fourth finance and central bank deputies' meeting (September 5-6), joint sherpa and finance deputies' meeting (September 6), joint finance and energy deputies' meeting (September 7), joint finance and energy ministers' meeting (September 8) and the main summit (September 8) – are slated to take place in September, forcing the authorities to plan and corrective measures in advance to prevent waterlogging.

On August 29, 2020, US secretary of state John Kerry got a taste of Delhi's traffic jams due to severe waterlogging, when his motorcade took nearly an hour to reach the Taj Mahal hotel from IGI airport on a rain-drenched day. It had become a major security concern as US media personnel travelling with Kerry had started tweeting about the dismal traffic situation in the city, prompting US and Indian intelligence officials to quickly review the security apparatus.

File photos

NOT A PRETTY PICTURE: With roads leading to IGI getting flooded everytime it rains heavily, the authorities have their hands full as they prepare to host dignitaries

Officials said several important steps have been planned in this regard. These include using AI-based predictive modelling and prediction systems, desilting in advance, re-carpeting of roads to ensure the gradient matches the drainage system, identification of common points where emergency crews can be stationed in case of waterlogging, improving the sewerage system and replacement and repair of old pipelines.

Cleaning of all stormwater drains on a regular basis, construction of retaining walls, wherever necessary, for minimising flooding, proper drainage on bridges, sensitisation of sanitation workers not to turn stormwater drains to dump sites and creation of ponds for holding excess water in case of heavy rains have also been planned.

TOI@G20

"The agencies have been given the deadline of June 2023 to complete these works," said a senior official.

"The first heavy downpour of the monsoon in June-end or July first week will be the litmus test. It will give us time to make necessary changes in case there is waterlogging," the official added.

Officials added that the area around IGI airport and Dwarka underpass is among several prominent road stretches prone to waterlogging during the monsoon. DDA has already started a major drainage project to channelise the rain and stormwater discharge from the airport to Najafgarh drain, which is likely to be completed by May 2023.

PWD has also made micro-level plans to deal with waterlogging hotspots, said another official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

अमर उजाला

अनधिकृत कॉलोनियों में तीन माह में पूरा होगा बचा विकास कार्य : सिसोदिया

दिल्ली सचिवालय में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। अमर उजाला

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रुका हुआ विकास कार्य अगले तीन माह में पूरा हो जाएगा। काम को जल्द से जल्द करवाने के लिए हर 15 दिनों में समीक्षा की जाएगी। सोमवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारियों के साथ विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां कुछ काम बचा हुआ है, उसे तीन माह में खत्म किया जाए। साथ ही बची कॉलोनियों में भी विकास कार्य जल्द शुरू किए जाएं।

दिल्ली सरकार ने पिछले 4 साल में 60 विधानसभा क्षेत्रों की करीब 1100 अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करने या फिर अपने अंतिम चरण में होने का दावा किया है। सरकार का कहना है कि इसके तहत इन कॉलोनियों में सड़कें, गलियां व नालियां बनवाने, सीवर व पानी की लाइनें डलवाने का काम किया गया है।

300 कॉलोनियों में नहीं हो पाया काम: अधिकारियों ने बताया कि करीब 300 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जहां विभिन्न कारणों की वजह से विकासात्मक कार्य नहीं किया जा सका। इन कॉलोनियों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, डीडीए से एनओसी न मिलने, फॉरेस्ट लैंड होने, ओवरलैपिंग होने के कारण दिल्ली सरकार द्वारा डेवलपमेंट कार्य शुरू नहीं किए जा सके। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि इन कॉलोनियों में बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं, जहां नालियों-गलियों की स्थिति पहले से ही अच्छी है या फिर उसे किसी अन्य एजेंसी द्वारा डेवलप किया गया है।

सरकार मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने को प्रतिबद्ध

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में 3767 किलोमीटर गलियों व 5203 किमी नालियों का निर्माण किया जा चुका है। सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने को प्रतिबद्ध है जबकि पहले की सरकार इनसे दूरी बनाती थी। पहले यहां रहने वालों की हालत काफी दयनीय थी। यहां जल-निकासी के लिए नालियां तक नहीं थीं। कच्ची सड़कें थी। बरसात के दौरान जगह-जगह पानी भर जाता था। आप सरकार ने संज्ञान लिया और इन कॉलोनियों का विकास किया।

20 दिसम्बर • 2022 | राष्ट्रीय सहारा

डीडीए को फिर नहीं मिले फ्लैटों के मुताबिक खरीदार

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के ऑन लाइन ड्रा में विशेष आवासीय योजना-2021 की प्रतीक्षा सूची में शामिल 235 आवेदक सफल रहे। ऑन लाइन ड्रा में डीडीए के फ्लैटों के प्रति एक बार फिर आवेदकों की बेरुखी सामने आयी है। दरअसल इस योजना में करीब 18 हजार फ्लैट शामिल थे, लेकिन आवेदकों की कमी को देखते हुए प्राधिकरण ने मुख्य ड्रा के आखिरी समय में फ्लैटों की संख्या कम कर दी थी।

विशेष आवासीय योजना-21 की प्रतीक्षारत सूची में डीडीए ने कुल 3544 फ्लैट सुरक्षित रखे थे। माना जा रहा था कि सभी को आवेदकों को फ्लैट मिल जाएंगे, लेकिन आवेदकों की बेरुखी के चलते डीडीए कुल 235 फ्लैट ही आवंटित कर सका। दिलचस्प बात यह है कि फ्लैटों के मुकाबले आवेदकों की संख्या काफी रही। प्राधिकरण की पिछली आवासीय योजनाओं को भी कमोवेश यही हाल रहा है। फ्लैटों के मुकाबले कम आवेदन आए हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि सफल आवेदकों ने फ्लैट खरीदने से मना कर दिया और अपनी पंजीकरण राशि वापस ले ली। हालांकि योजना के ऑन लाइन ड्रा में पूरी पारदर्शिता रखी गयी। पूर्व न्यायाधीश के पैनल की उपस्थिति में ड्रा निकाला गया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | TUESDAY, 20 DECEMBER, 2022 ----------DATED----------

'DELHI GOVT IS DETERMINED TO PROVIDE BASIC CIVIC INFRASTRUCTURE'

Sisodia: Complete dev works in unauthorised colonies in 3 mths

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Deputy Chief Minister Manish Sisodia Monday directed officials to complete within three months the pending road construction and laying of drainage system in unauthorised colonies of Delhi.

According to officials, of the 1,800 unauthorised colonies, development works in about 1,100 are either in their final stages or have been completed.

Sisodia reviewed the ongoing road construction and laying drainage system in the unauthorised colonies along with the senior officials of the Irrigation and Flood Control Department and the Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation.

During the review meeting, officials said development work could not be carried out in about 300 unauthorised colonies and cited various reasons, including the unavailability of no objection certificate from the archaeological department and the Delhi Development Authority, the region being attributed as forest land, and overlapping. Also, some of them are already developed and have the basic civic infrastructure, or they are being developed by other agencies, the officials added.

During the review meeting, officials said development work could not be carried out in about 300 unauthorised colonies and cited various reasons

Sisodia, who also holds the PWD portfolio, directed officials to complete the pending works in the next three months which include construction of roads and drains, the installation of sewer and water pipes in these colonies. Development works in remaining colonies will be started soon, officials said.

The deputy chief minister instructed the officials to complete the developmental work of the remaining colonies on priority, which will be reviewed by him every 15 days.

"The Delhi government is determined to provide basic civic infrastructure to the residents of unauthorised colonies. Previous governments considered the unauthorised colonies as vote banks only and never paid attention to their development after election. Unlike others, the Delhi government is determined to fulfil its guarantees to develop quality civic infrastructure in these colonies," Sisodia said.

Highlights

- » According to officials, of the 1,800 unauthorised colonies, development works in about 1,100 are either in their final stages or have been completed
- » Sisodia reviewed the ongoing road construction and laying drainage system in the unauthorised colonies along with the senior officials
- » Complete the developmental work of the remaining colonies on priority, which will be reviewed by him every 15 days: Sisodia